शोध मंथन Vol. XI No.III July-Sept. 2020 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 7.760 (SJIF)

शहरीकरण – कारण, दुष्प्रभाव एवं सरकारी प्रयास

डा0 शिवानी
राजनीतिशास्त्र विभाग
डी०ए०वी० सैन्टनरी कॉलिज फरीदाबाद
Email:shivanitanwar1973@gmail.com

सारांश

दुनियां में बढ़ते औद्योगिकीकरण और विशेषकर द्वितिय विश्व युद्ध के बाद से शहरीकरण की प्रवृति देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रो से जनसंख्या का पलायन शहरो की तरफ हो रहा है। इसके पीछे शहरी क्षेत्रो मे उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व अन्य चमक–दमक या रोज़गार की तलाश में आने की मजबूरी कही जा सकती है। यद्यपि किसी देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उस देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का प्रतीक होता है परन्तु इसके साथ ही यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आय व रोजगार, यातायात व संचार की सुविधाओ का अभाव, जल, थल एवं वायु प्रदूषण तथाअनेक प्रकार की चोरी, डकैती, हत्याऐं, बलात्कार, भ्रष्टाचार, हड़ताले, वैश्यावृत्ति जैसी समस्याऐं भी समेटे हुए है, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक अव्यवस्था व अराजकता को बढ़ावा मिलता है। प्रस्तुत लेख में शहरीकरण किस प्रकार से आर्थिक विकास का प्रतीक है? किन कारणों से शहरीकरण बढ़ रहा है? शहरीकरण के क्या–क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे है तथा शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओ पर नियन्त्रण करने की दिशा में सरकार द्वारा किन–किन योजनाओ को चलाया जा रहा है? यहां पर इन सब महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर प्रकाश डाला गया है।

<u>मुख्य शब्दः</u> *औद्योगिकीकरण, पलायन, भ्रष्टाचार, शहरीकरण।*

प्रस्तावना

आज दुनियां के सभी देशो में शहरीकरण की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। शहरीकरण का विस्तार विशेष रूप से औद्योगिक क्रान्ति के बाद से शुरू हुआ है। विकास प्रक्रिया में उद्योग धन्धों की स्थापना की वजह से यहां पर लोगो को रोज़गार व आय के अवसर प्राप्त होते है। अतः यहां पर काम करने वाली मानव शक्ति का संकेन्द्रीकरण होने से शहर बस जाते है।

इस प्रकार कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगो का व्यापार, उद्योग एवं निर्माण कार्यो के लिए शहरो में जाकर रहना व काम करना शहरीकरण कहलाता है।

भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार शहरी क्षेत्रो को निम्नलिखित रूप मे परिभाषित किया गया हैः–

1 वे सभी स्थान, जिसमे नगरपालिका या नगर निगम,छावनी बोर्ड या नोटिफाइड एरिया कमेटी है।

2 वे सभी स्थान, जा निम्नलिखित शर्तो को पूरा करते हैः–

3 जिनकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो।

4 जिसकी कार्यकारी जनसंख्या का 75% भाग गैर–कृषि कार्यो जैसे उद्योग, निर्माण, यातायात आदि मे लगा हुआ हो।

5 जिसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो ।

उपरोक्त शर्तो के अलावा शहरी क्षेत्र के लिए उद्योग, व्यवसाय, बड़ी आवासीय बस्तियो, बिजली–पानी व सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था होना भी जरूरी है।

शहरीकरण विकास का प्रतीक (Urbanization as an Indicator of Growth)

शहरी क्षेत्रों मे कृषि अथवा ग्रामीण क्षेत्रो की तुलना मे रोजगार व व्यापार की सम्भावनाऐं अधिक होती है।

- आज दुनिया की कुल आबादी का 54% हिस्सा शहरो मे निवास करता है।
- विश्व के कुल उत्पादन व आय मे 80% हिस्सा इन्ही क्षेत्रो से प्राप्त होता है।
- लगभग दो–तिहाई वैश्विक ऊर्जा की खपत शहरो मे ही होती है।
- 70% ग्रीन हाऊस गैसो के उत्सर्जन के लिए भी शहरी क्षेत्र जिम्मेदार है।
- यह क्षेत्र विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित गतिविधियों का केन्द्र होते है।
- यह अलग–अलग संस्कृतियों और परम्पराओ को समझने का अनूठा स्थल होते है।
- भारत की कुल आबादी का लगभग 33% हिस्स शहरी क्षेत्रो मे निवास करता है।
- सन् 2050 तक भारत की कुल आबादी का 50% हिस्सा शहरीकरण होगा तथा
- विश्व की कुल जनसंख्या का 2050 तक 70% हिस्सा शहरी क्षेत्रो मे होने का अनुमान

भारत में बढ़ते शहरीकरण के कारण (Causes of Incerasing Urbanisation in India)

भारत में शहरीकरण को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैः–

1. औद्योगिकीकरण

   शहरीकरण और औद्योगिकीकरण मे प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाया जाता है अर्थात् औद्योगिकीकरण बढ़ेगा तो शहरीकरण भी बढ़ेगा। किसी स्थान पर बड़े–छोटे उद्योगो की स्थापना से वहां पर लोगो को अनेक प्रकार के रोज़गार के अवसर प्राप्त होते है जिससे लोग यहां पर आकर बस जाते है।

2. कृषि पर बढ़ता जनसंख्या दवाब

जनसंख्या वृद्धि से परिवार के सदस्यो की संख्या बढ़ने से भूमि के उपविभाजन एवं विखण्डन

की समस्या बढ़ती है जिससे भूमि के छोटे–छोटे आंकड़ो पर कृषि कार्य करना लाभदायक नही रह जाता है। दूसरे हमारी कृषि मानसून पर निर्भर करती है अतः सूखे की स्थिति में किसान की हालात दयनीय हो जाती है और वे कृषि से विमुख होकर रोजगार की तलाश मे शहरो की ओर रूख कर लेते हैं।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरो की कमी

एक तरफ तो कृषि अब लाभकारी व्यवसाय नही रहा है, दूसरे ग्रामीण क्षेत्रो मे सड़के, बिजली, यातायात एवं अन्य आधारभूत ढ़ांचे का अभाव पाया जाता है जिससे वहां पर किसी प्रकार के कुटीर और लघु उद्योग लगाना सम्भव नही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रो मे पूंजी का अभाव होना भी एक कारण है।

4. बुनियादी सुविधाओ का होना

शहरी क्षेत्रो मे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साथ–साथ यातायात एवं संचार की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रो की तुलना मे बेहतर होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रो में जो भी परिवार आर्थिक रूप से सम्पन्न हो जाते हैं वे इन सुविधाओं और आरामप्रद जीवन के लालच मे शहरों में प्लाट या फ्लैट खरीद कर वहां पर रहने लग जाते है।

5. शिक्षा व रोजगार के अवसर

शहरी क्षेत्रों में उद्योग, व्यवसाय व व्यापारिक क्रियाओं की वजह से लोगो को यहां रोजगार मिल जाता है। दूसरे देश के बड़े और उच्च शिक्षण संस्थान शहरों में ही होते हैं सो ग्रामीण इलाकों से विद्यार्थी यहां पर पढ़ने आते हैं और बाद में रोजगार भी प्राप्त करके शहरों में ही निवास करने लग जाते है।

6. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण

1991 के बाद से आर्थिक उदासीकरण की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित क्षेत्रों में स्थापित लघु व कुटीर उद्योग धंधे लगभग चौपट हो गये। इससे लोग बेरोजगार हो गये और वे रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन को मजबूर हो रहे हैं। दूसरे वैश्विकरण के कारण देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश हो रहा है। इन कम्पनियों ने गुड़गांव, नोएडा, बंग्लौर, हैदराबाद, पूणे, मैसूर जैसे बड़े–बड़े शहरों में अपने कार्यालय खोल रखे हैं। जिसमें लाखों की संख्या में देश के युवा कार्य करते हैं और स्वभाविक है कि यहां काम करने आएंगे तो रहना भी यही होगा। इससे भी शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।

उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त सुरक्षा की भावना व उच्च जीवन स्तर की लालसा जैसी कुछ कारण हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर खींच कर लाते हैं। संक्षेप में, बढ़ते शहरीकरण के पीछे तीन प्रमुख कारण कहे जा सकते हैं–पहला, जनता का शहरीकरण सुविधाओं के प्रति

आकर्षण का होना। दूसरा, कुछ लोग की आर्थिक व सामाजिक मजबूरियां होती हैं तथा तीसरे किसी विशेष उद्धेश्य की प्राप्ति हेतु शहरों की ओर पलायन है।

शहरीकरण के प्रभाव (Effects of Urbanization)

जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते है उसी प्रकार शहरीकरण भी जैसे एक तरफ लोग की आय, रोजगार व जीवन स्तर मे सुधार लाता है तो दूसरी तरफ पर्यावरणीय, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा अन्य सामाजिक व नैतिक समस्याऐ भी पैदा होती है। इसका वर्णन हम निम्नलिखित दो भागो मे कर सकते हैः–

A) शहरीकरण के लाभ (Merits of Urbanization)

B) शहरीकरण की हानियां (Demerits of Urbanization)

शहरीकरण के लाभ (Merits of Urbanization) :-

a) आर्थिक विकास –

शहरो मे उद्योग व अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते है इससे लोगो की आय, उपभोग, बचत, निवेश तथा पूंजी निर्माण शक्ति मे बढ़ौतरी होती है जो और आगे उत्पादन बढ़ाने मे सहायक होता है।

ii) कृषि क्षेत्र को लाभ

ग्रामीण इलाको से जनसंख्या शहरो की ओर जाने से कृषि भूमि पर दवाब में कमी आती है। जिससे प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन में बढ़ौतरी होती है और किसान की आर्थिक स्थिति मे सुधार सम्भव होता है।

iii) उच्च जीवन स्तर

शहरी लोगो को शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई की अच्छी सुविधाऐं मिलने से उनकी जीवन प्रत्याशा आयु में वृद्धि सम्भव हो पाती है। इससे उनकी कार्य क्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कारक होता है।

iv) सोच में बदलाव

गाँव से लोग शहरो मे आकर वहां की संस्कृति से प्रभावित होकर, अपने पुराने रूढ़ीवादी तथा अन्ध विश्वासी दृष्टि कोणो को छोड़ पाते है, जो कि उनकी आर्थिक प्रगति में बाधक थे। शिक्षा की वजह से उनका दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक और तार्किक बनता है जो आर्थिक विकास मे सहायक होता है।

B) शहरीकरण की हानियां (Demerits of Urbanization)

शहरीकरण से जहां एक ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, आय व रोजगार मे वृद्धि से देश का आर्थिक विकास सम्भव होता है वही दूसरी तरफ अनियोजित एवं अनियन्त्रित शहरीकरण से बहुत सारी समस्याऐं भी पैदा होती है। जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

i) बुनियादी सुविधाओ में कमी

शहरों में जनाधिक्य होने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व संचार सुविधाओं की मांग को देखते हुए उस अनुपात में सह सब उपलब्ध नहीं हो पाता है।

ii) रोजगार का अभाव

जिस तेज गति से शहरों में लोगो की जनसंख्या बढ़ रही है। उस हिसाब से लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जिससे बेरोज़गारी व गरीबी को बढ़ावा मिलता है।

iii) ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रोंमें जों कुछ काबिल, सक्षम एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वे शहरों में चले जाते हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचती है। दूसरी ओर इन लोगों को शहरों में भी सही रोजगार उपलब्ध नही हो पाता है जिससे मानवीय संसाधनों का अपव्यय होता है।

iv) पर्यावरण प्रदूषण की समस्या

शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण, यातायात के साधनों व सीवेज व्यवस्था पर अधिक भार पड़ता है परिणाम स्वरूप ध्वनि और जल प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में फैक्ट्रियों की भी अधिकता पाई जाती है जो वायु प्रदूषण को जन्म देती है।

C) अपराधो की संख्या मे बढ़ौतरीः–

शहरों में बढ़ती हुई आबादी के साथ–साथ ही चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, हड़ताल, जुआ, वैश्यावृत्ति व शराब पीने की घटनाओं में वृद्धि होती है जिससे सामाजिक अव्यवस्था व अराजकता फैलती है।

मलिन बस्तियां (Slums)

शहरी क्षेत्रों जहां एक तरफ बड़ी ऊंची–ऊंची इमारते, सुन्दर एवं आलिशान बंगले देखते हैं तो दूसरी तरफ इनके आजू–बाजू में बनी हजारो की तादात में झुगियां भी किसी से छुपी नही रहती है। ये सामान्यता ग्रीन बेल्ट, रेलवे लाईनो, सड़को व नहरों के किनारे बनी हुई होती है तथा पूर्ण रूप से अवैध व गैर कानूनी होती है। देश में वोट की राजनीति होने की वजह से कोई भी सरकार इनको हटाने का प्रयास नहीं करती है बल्कि इनको बढ़ावा देती है। इन बस्तियों में प्रायः दिहाड़ी मज़दूर और छोटे व्यवसायी रहते है। इनमें रहने वाले लोगो की संस्कृति, भाषा, धर्म, परम्पराऐं व रिवाज भले ही भिन्न–भिन्न हो परन्तु मुख्य कारक आर्थिक होता है जो इन्हे एक स्थान पर इक्टठा कर देता है।

गरीबी व मजबूरी की वजह से ये मलिन बस्तिया जुआ, शराब खोरी, चोरी, वैश्यावृत्ति, बलात्कार जैसी असामाजिक गतिविधियो के अड्डे होते है। यहां पर बिजली व पानी चोरी जैसी घटनाऐ आम बात होती है। कुछ अपराधी एवं दबंग प्रवृति के लोगो द्वारा इन बेबस व मजबूर लोगो से अवैध वसूलियां भी की जाती है। इन लोगो का जीवन पूर्ण रूप से नरकीय होता है।

शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए सरकारी प्रयास (Government Efforts to Tackle the Problems of Urbanisation)

हमारा शहरी विकास तन्त्र उतना अच्छा नहीं है जितना की इसको होना चाहिए। इसके पीछे समुचित शहरी नीति का अभाव होना, अनुचित शहरी नियोजन, आर्थिक संसाधनो का अभाव, जवाबदेही एवं पारदर्शिता का अभाव तथा विभिन्न विभागो जैसे जन स्वास्थ्य, बिजली–पानी, तथा यातायात आदि के बीच असमन्वय का अभाव का होना है। इसलिए समुचित शहरीकरण के लिए पर्याप्त ढ़ांचे जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़के, यातायात व संचार व्यवस्था, रोजगार, सफाई व शुद्ध पर्यावरण हेतु प्रबन्धन की आवश्यकता है।

इस दिशा में भारत सरकार जून तथा अगस्त 2015 मे कुछ महत्वाकांशी योजनाओं का प्रारूप तैयार किया गया है। हम आशा करते हैं शहरीकरण में कुछ सुधार सम्भव होगा। सरकार की प्रमुख योजनाऐ निम्न प्रकार से हैः–

1. शहरी रूपान्तरण एवं नवीनीकरण अटल मिशन
2. स्मार्ट शहर मिशन
3. '2022 तक सभी के लिए आवास' मिशन

1. शहरी रूपान्तरण व नवीनीकरण–अटल मिशन (Urban Transformation & Renewal-Atal Mission)

25 जून 2015 को केन्द्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है इसमे देश में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों व कस्बों में से 500 का चयन किया जाएगा तथा साथ ही प्रमुख नदियों, राजधानियों, पवर्तीय क्षेत्रों, द्वीपों और मुख्य पर्यटन स्थलो को भी इसमे शामिल किया जाएगा। इन शहरो में पर्याप्त मात्रा में सड़को, सीवेज व्यवस्था, बिजली–पानी, शिक्षा–स्वास्थ्य, यातायात तथा संचार व्यवस्था की जाएगी। ताकि यहां पर निवास करने वाले लोगो के जीवन की गुणवत्ता मे सुधार सम्भव हो सके।

2. स्मार्ट शहर मिशन (Smart City Mission)

27 अगस्त,2015 को उपरोक्त योजना की तर्ज पर ही देश के अन्दर एक 'सिटी चैलेंज प्रतियोगिता' के आधार पर कुछ 100 शहरो का चयन किया जाएगा और प्रत्येक शहर को उसकी शहरी ढ़ांचागत व्यवस्था मे सुधार के लिए प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी ताकि वित्तीय संसाधनो के चलते शहरवासियों को सीवेज, परिवहन, सड़को व अन्य समस्याओ से जुझना न पड़े।

3. 2022 तक सभी के लिए आवास मिशन (Housing for All in 2022, Mission)

शहरी आवास हेतु इस मिशन को 'प्रधानमन्त्री आवास योजना' का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत शहरो मे रहने वाले गरीब लोगो के अगले 7 वर्षो मे 2 करोड़ आवासो का

निर्माण किया जाएगा। ताकि इन लोगो को झुग्गियों और मिलन बस्तियों से निजात मिल सके और अपने नरकीय जीवन से निकल सके।

सार स्वरूप सरकार की ये सभी योजनाऐं बहुत अच्छी है बशर्ते कि इनका क्रियान्वयन ईमानदारी से किया जाए। सच कहे तो इन योजनाओं का 50% पैसा सही मायने में, उचित लाभार्थियों तक भी पहुंच पाए तो भी एक बड़ी बात होगी और योजनाऐं अपने लक्ष्य प्राप्ति को फलीभूत होती नज़र आएगी।

आगे क्या किया जा सकता है? (What Should be Option?)

शहरीकरण से बढ़ती समस्याओं पर नियन्त्रण पाने के लिए हमें शहर के आकर्षण के प्रति लोगो की सोच बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली–पानी, शिक्षा–स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओ को बढ़ाना होगा तथा साथ ही वहां रोज़गार के अवसर भी तलाशने होंगे ताकि शहरों में जनसंख्या का दबाव कम किया जा सके। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास सम्भव हो सकते हैं।

- → ग्रामीण क्षेत्रो में रोज़गार के अवसर पैदा करके उनके शहर की ओर पलायन को रोका जाए। मनरेगा इस दिशा मे कारगर सिद्ध हो सकता है।
- → ग्रामीण क्षेत्रो में बुनियादी सुविधाओ को बढ़ाना होगा।
- → शहरो को स्थानीय नियोजन और सार्वजनिक उपयोगता के जरिये उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
- → शहरी स्थानीय निकायों को और वित्तीय शक्तियां प्रदान करनी होगी।
- → धारणीय, समावेशी तथा तीव्र संवृद्धि को प्रोत्साहित करना होगा।
- → राजकोषीय वितरण एवं विकास कार्यों हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था करना।
- → भ्रष्टाचार व रिश्वत खोरी पर नियन्त्रण हेतु ऑन–लाईन जैसी व्यवस्थाओ के जरिये पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा।
- → उपलब्ध भूमि एवं वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढ़ंग से प्रबन्धन करना होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. अग्रवाल ए0एन एवं अग्रवाल एस0 के, *''भारतीय अर्थव्यवस्था,''* न्यू ऍज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. गुप्ता एस0एन, *''जनांकिकी के मूल तत्व,''*हिमालया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
3. मलैया के0सी0 एवं शर्मा रमा, *''जनसंख्या शिक्षा''*, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा (यू0पी0)
4. पूरी वी0के0 एवं मिश्रा एस0 के, *''भारतीय अर्थव्यवस्था''*, हिमालय पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
5. साहू वी0के0, *''पॉपुलेशन एजुकेशन'*, स्ट्रीलंग पब्लिशर्सज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. वांगु एम0एल0, *''पॉपुलेशन एजुकेशन'',* टण्डन पब्लिकेशन्स, लुधियाना (पंजाब)।